

# सामाजिक विकास एवं सामाजिक नीति

## सामाजिक नीति

सामाजिक नीति का तात्पर्य ऐसे नियमों से है जिनके द्वारा सरकार के हितों की अभिव्यक्ति होती है और जिसके अनुरूप सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। स्पष्ट है सामाजिक नीति सामाजिक संरचनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार एवं औपचारिक संगठनों द्वारा निर्मित नियम है जो राज्य या सरकार के हितों को अभिव्यक्त करता है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। अवधारणात्मक स्तर पर सामाजिक नीति केवल विकास की नीति को ही नहीं दर्शाता बल्कि इसमें उन सभी नीतियों को शामिल किया जाता है जो राज्य या समाज अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्धारित करते हैं। परंतु हाल के वर्षों में इसको योजनाबद्ध परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में ही विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

किसी भी देश में नियोजित परिवर्तन द्वारा सामाजिक विकास लाने के लिए सामाजिक नीति कैसी हो यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-राष्ट्रीय विचारधारा, भिन्न-भिन्न समूहों के विशिष्ट उद्देश्य, राष्ट्र के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन और उनके दोहन की परिसीमा आदि। एक राष्ट्र की सामाजिक नीति का निर्णायक रूप से निर्धारण तब तक संभव नहीं है जब तक कि राष्ट्रीय परिस्थितियों का सही रूप से मूल्यांकन न कर लिया जाए। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि नियोजन को कितने

प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। अपूर्ण सामाजिक नीति होने से राष्ट्रीय संसाधनों का न तो अच्छी तरह दोहन किया जा सकता है बल्कि उनकी क्षति भी हो जाती है।

अतः निष्कर्ष है कि सामाजिक नीति योजनाबद्ध परिवर्तन का पूर्व आधार है और राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है परंतु इसकी सफलता हेतु आवश्यक है कि उपरोक्त तथ्यों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मांगों को भी ध्यान में रखा जाए।

## सामाजिक विकास

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन के एक विशिष्ट स्वरूप तथा प्रक्रिया के रूप में सामाजिक विकास की अवधारणा काफी लोकप्रिय रही है। सामाजिक विकास सामाजिक परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च-भौतिक रहन-सहन के स्तर, स्वास्थ्य के स्तर एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार तथा अधिकाधिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सामाजिक विकास कहते हैं।

सामान्यतः सामाजिक विकास के अंतर्गत निम्न लक्ष्यों को प्रमुखता दी जाती है -

1. आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार (भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में) होना चाहिए अर्थात् जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए।
  2. संसाधन, लाभ एवं आय का समान वितरण होना चाहिए, अर्थात् सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  3. शक्ति के केन्द्रीकरण पर रोक या शक्ति के विकेन्द्रीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
  4. मानव संसाधनों का विकास होना चाहिए।
- स्पष्ट है सामाजिक विकास के साथ सामाजिक न्याय को भी जोड़ा गया है जिसका तात्पर्य है कि अन्यों (समृद्ध व्यक्तियों की) की अपेक्षा सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विकास की नीतियों और स्वरूपों का अधिक लाभ मिले। सम्प्रति सामाजिक विकास के नए विकल्पों की खोज भी जारी है जिसमें गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, ऊर्जा के नए स्रोतों का ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना को प्रमुखता दी जा रही है।

विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर एकमत्यता नहीं है। फलतः मोटे रूप में विकास के तीन प्रमुख मॉडलों का रूप देखने को मिलता है -

1. पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल
2. समाजवादी मॉडल
3. मिश्रित मॉडल

इनमें से पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल आज सर्वाधिक प्रचलित मॉडल है, जिसको वर्तमान में अधिकांश देशों द्वारा अपनाया जा रहा है और सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास जारी है।

## सामाजिक विकास या सामाजिक नीति का स्वरूप

किसी भी विकासशील देश के विकास एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु सामाजिक नीति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इस सामाजिक नीति से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसका सापेक्षिक होना और इसके निर्माण में कई आधारभूत तत्वों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे -

1. सर्वप्रथम राष्ट्रीय परिस्थितियां, विचारधारा, राष्ट्र के संसाधनों एवं अंतर्राष्ट्रीय मांगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2. उत्पादन वृद्धि को सुनिश्चित करने वाला एक प्रभावशाली आर्थिक कार्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रियाओं का जिस तेजी से विकास हुआ है उससे यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक राष्ट्र सामाजिक विकास के लिये ऐसी नीति तैयार करे जिसमें मानव द्वारा सुरक्षा की पूरी गारंटी हो।
3. यह सिद्ध हो चुका है कि तीसरी दुनिया की अधिकांश समस्याओं की जड़ में गरीबी है, अतः सर्वप्रथम निरपेक्ष गरीबी को और उसके बाद सापेक्ष गरीबी को समाप्त करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. सामाजिक नीति के निर्माण में सामाजिक न्याय के पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना आदर्श समाज के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।
5. शोषण और दमन को पुष्ट करने वाली विद्यमान पारस्परिक सामाजिक रचनाओं को समाप्त करना चाहिए।

6. विकास संबंधी नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में लोकतंत्रीकरण एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि बिना इसके अवसरों की समानता सही रूप में नहीं लाई जा सकती है।
7. लक्ष्यों के निर्धारण एवं कार्यक्रमों के संचालन में समाज के सांस्कृतिक पक्षों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए।
8. विकास के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः सामाजिक नीति में पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी केन्द्रित होने चाहिए।

## A सामाजिक विकास में सामाजिक नीति की भूमिका

सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार-तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही सामाजिक विकास है जो योजनाबद्ध प्रयासों द्वारा संभव होती है। जबकि सामाजिक नीति के अंतर्गत सरकार के हितों को अभिव्यक्त करने वाले ऐसे नियम शामिल हैं जो योजनाबद्ध परिवर्तन हेतु प्रमुख निर्देशक का काम करते हैं। बिना सामाजिक नीति के सही दिशा में सामाजिक विकास संभव नहीं है क्योंकि यह सामाजिक विकास में योजनाओं के स्वरूप के निर्धारण, इसकी रणनीति का निर्माण और इसके क्रियान्वयन हेतु निर्देशक का काम करती है।

सामान्यतः सामाजिक विकास सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है परंतु इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर एकमत्यता नहीं है। इसलिए विभिन्न देशों द्वारा सामाजिक विकास के अलग-अलग मॉडलों को अपनाया जा रहा है। सामाजिक विकास के मॉडल सामाजिक नीति के मॉडल को निर्धारित करते हैं जो उदारवादी-पूँजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल या मिश्रित मॉडल हो सकते हैं।

एस. सी. दुबे का मानना है कि किसी देश में सामाजिक विकास के लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक विकास की प्रक्रिया का समाज की गैर-आर्थिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य बना रहे। सामाजिक विकास की नीति सामाजिक संरचना की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है जिससे सामाजिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो जाता है।

सामाजिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि नियोजन और विकास की कितनी क्षमता राष्ट्र के पास है और नियोजन एवं विकास को कितने प्रभावकारी ढंग से

लागू किया जाता है। आधे-अधूरे मन से या गलत सामाजिक नीति से राष्ट्रीय संसाधनों का सही ढंग से दोहन भी नहीं हो पाता है और इनका अपव्यय भी होता है। चूंकि सामाजिक नीति का निर्माण राष्ट्र की आवश्यकताओं, उपलब्ध स्रोतों, मानव संसाधनों और योजनाओं के संभावित परिणामों के मूल्यांकन के पश्चात् किया जाता है। फलतः नियोजित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का संचालन सफलतापूर्वक संभव हो पाता है तथा सामाजिक विकास के नकारात्मक परिणामों की संभावना भी सीमित हो जाती है।

प्रत्येक समाज की एक विचारधारा होती है तथा कोई भी सामाजिक विकास की प्रक्रिया इसकी पूर्णतः अवहेलना करके सफल नहीं हो सकती। (1977 की जनसंख्या नीति) सामाजिक नीति समाज में प्रचलित विचारधारा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यदि किसी नवीन विचारधारा का आरोपण सामाजिक विकास के लक्ष्यों में निहित है तो सामाजिक नीति ऐसी योजनाओं को संपोषित करती है जो नवीन विचारधारा को प्रसारित करे, उसका जनाधार तैयार करे और परिवर्तन की प्रक्रिया से सामंजस्य बना रहे ताकि सामाजिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

सामाजिक विकास के लिए सामाजिक नीति तब और भी आवश्यक हो जाती है जब सामाजिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तथा हर क्षेत्र तक पहुंचाना हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में समाजवाद इसका लक्ष्य है। फलतः सामाजिक नीति में सामाजिक न्याय की प्राप्ति को यहां सदैव प्रमुखता दी जाती रही है। अतः सामाजिक नीति का उद्देश्य न केवल विकास का लाभ जन-जन तक पहुंचाना होता है अपितु सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना होता है।

स्पष्ट है कि अनुकूल सामाजिक नीति ही सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। असंगत एवं प्रतिकूल सामाजिक नीति का निर्माण न केवल सामाजिक विकास के लक्ष्य को दूर कर देता है, अपितु लक्ष्य प्राप्ति में अवरोधक भी बन जाता है।

## M 54 सामाजिक विकास एवं निर्भरता

अविकसित एवं विकासशील देशों का तकनीकी एवं आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में विकसित देशों निर्भरता को सामाजिक विकास के संदर्भ में 'निर्भरता' की अवधारणा द्वारा स्पष्ट किया